भारत सरकार

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4331

बुधवार, दिनांक 26 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>तमिलनाडु में सौर ऊर्जा</u>

4331. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसादः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में सौर ऊर्जा का दोहन किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुड्डालोर और आसपास के जिलों, जहाँ गर्मियों में अधिक तापमान रहता है, में घरेलू उपयोग हेतु सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की गई है अथवा प्रस्तावित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या तमिलनाडु में बिजली के उपयोग में कमी लाने के लिए सरकारी महाविद्यालयों, विद्यालयों, कार्यालयों में सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (ग): सरकार ने तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले सहित देश में सौर विद्युत का दोहन करने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है। क्रियाशील योजनाओं की सूची अनुलग्नक में दी गई है।

प्रधान मंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के घटक-ख के तहत, दिनांक 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में 80 स्टैण्डअलोन ऑफ ग्रिड सौर जल पंप स्थापित किए गए हैं।

पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीः एमबीवाई) के तहत, दिनांक 19.03.2025 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय पोर्टल पर कुल 3118 आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं और तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में 412 परिवार रूफटॉप सौर संयंत्र की स्थापना से लाभान्वित हुए हैं।

(घ) पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना के तहत, कॉलेजों, स्कूलों, कार्यालयों, आदि सहित सरकारी भवनों को रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली के माध्यम से परिपूर्ण करना इस योजना के घटकों में से एक है। इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जो विभिन्न कार्यान्वयन मॉडल प्रदान करते हैं और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की तैनाती में अनुभव रखने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) को केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने भवनों पर रूफटॉप सौर स्थापित करने में सहायता करते हैं।

अनुलग्नक

'तमिलनाडु में सौर ऊर्जा' के संबंध में पूछे गए दिनांक 26.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4331 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

देश में सौर विद्युत को बढ़ावा देने के लिए कार्यशील योजनाओं की सूची

1. 40,000 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लक्ष्य के साथ सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए योजना। इस योजना के तहत भूमि, सड़क, विद्युत निकासी प्रणाली, जल की सुविधाएं जैसी अवसंरचना सभी सांविधिक स्वीकृतियों/अनुमोदनों के साथ विकसित की जाती हैं। इस प्रकार, यह योजना देश में उपयोगिता-स्तर की सौर परियोजनाओं के शीघ्र विकास में मदद करती है।
2. रूफटॉप सौर की स्थापना और एक करोड़ घरों के लिए प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना।
3. उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों (भाग-I और II) में गीगावाट स्तर की उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए "राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम" नामक उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना।
4. छोटे ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्रों, स्टैण्ड-अलोन सौर चालित कृषि पंपों और मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों के सौरीकरण को बढ़ावा देने के लिए पीएम-कुसुम योजना। यह योजना न केवल किसानों के लिए, बल्कि राज्यों और डिस्कॉमों के लिए भी लाभदायक है। राज्यों को कृषि उपभोक्ताओं को बिजली पर दी जा रही सब्सिडी की बचत होगी और डिस्कॉमों को सस्ती सौर विद्युत मिलेगी, जिससे अंत में पारेषण एवं वितरण हानियाँ नहीं होंगी।
5. सरकारी उत्पादकों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए अथवा सरकार/सरकारी संस्थाओं के उपयोग के लिए सीधे अथवा वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के माध्यम से व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता के साथ 12000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) की योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)।
6. ऑफ-ग्रिड सौर लाइटिंग प्रदान करने के प्रावधान के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बसाहटों/गांवों के लिए), जहाँ ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

*****